www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 125 | जौनपुर शुक्रवार, 19 दिसम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

उच्च न्यायालय ने ऑटो–टैक्सी किराया अधिसूचना पर अमल को लेकर सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों द्वारा वसूले जाने वाले किराए से संबंधित 2023 की अधिसूचना पर अमल को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अधिकारियों से यह जानकारी देने को भी कहा कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों द्वारा किराया वसूलते समय नियमों के उल्लंघन के लिए कितने चालान जारी किए। न्यायालय ने दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और उप पुलिस आयुक्त (यातायात) को नोटिस जारी कर कहा कि वे उस याचिका पर वस्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसमें सभी ऑटो रिक्शा चालकों के बीच सार्वजनिक आदेश(अधिसूचना) को तत्काल प्रभाव से या एक माह के भीतर लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने कहा, अपनी वस्तुस्थिति रिपोर्ट में, यह बताएं कि कितने चालान जारी किए गए हैं, आपकी मानक संचालन प्रक्रिया क्या है, शिकायत निवारण तंत्र क्या है और दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी नौ जनवरी, 2023 की अधिसूचना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

पंजाब–चंडीगढ़ में सड़क से आसमान तक घना कोहरा

चंडीगढ़, (एजेंसी)। पंजाब और चंडीगढ़ में घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। सड़कों के साथ–साथ आसमान में भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह घना कोहरा पड़े रहने की संभावना है। घने कोहरे का असर हवाई यातायात पर भी साफ दिखाई दे रहा है। बुधवार को तीन फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं, जबकि दो फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया। जयपुर और दिल्ली जाने वाली दो उड़ानें रद्द की गईं, वहीं दिल्ली और जयपुर से आने वाली दो फ्लाइट्स चंडीगढ़ नहीं पहुंच सकीं। सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के बाद दिन चढ़ने पर धूप निकलने से कुछ हद तक राहत मिल रही है। दिन में ठंड का असर कम रहता है, लेकिन रात और सुबह के समय सर्दी बढ़ जाती है। सर्द रातों के कारण लोग सड़कों के किनारे आग जलाकर ठंड से बचने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अभी भी बड़ा अंतर बना हुआ है। रोपड़ में अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि होशियारपुर में न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा।

सीएम योगी की पहल से अमेठी बना उन्नत स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा का हब

अमेठी, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। अमेठी की तिलोई तहसील में स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा इस महाविद्यालय का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वर्तमान में महाविद्यालय से संबद्ध 200 बेड वाले अस्पताल में सेवाएं संचालित हैं, जबकि 31 जनवरी 2026 तक 300 बेड का नया अस्पताल और 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक हैंडओवर किया जाएगा। इससे कुल बेड की संख्या 550 हो जाएगी, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही नर्सिंग कॉलेज का निर्माण भी इसी तिथि तक पूरा होने की उम्मीद है। योगी सरकार की यह पहल अमेठी सहित आसपास के जिलों के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। क्षेत्रवासियों का लंबे समय से चला आ रहा मेडिकल कॉलेज का सपना अब साकार हो रहा है और 2026 तक यह संस्थान पूर्ण रूप से 500 प्लस बेड वाले आधुनिक चिकित्सा केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। एमबीबीएस कोर्स में 100 सीटें स्वीकृत हैं। पैरामेडिकल क्षेत्र में 11 डिप्लोमा कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिनमें कुल 230 सीटें हैं। इनमें एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इमरजेंसी एवं ट्रॉमा केयर, लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन, एक्स–रे टेक्नीशियन जैसे महत्वपूर्ण कोर्स शामिल हैं। आगामी सत्र 2026–27 से बीएससी नर्सिंग कोर्स में 60 सीटें शुरू होने की तैयारी है। पोस्टग्रेजुएट स्तर पर डीएनबी कोर्स में प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग, एनेस्थीसिया में डिप्लोमा और मेडिसिन में डिग्री कोर्स स्वीकृत हैं।

मोहन भगवत सिलीगुड़ी में युवा सम्मेलन को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन राव भागवत आज सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित शताब्दी सदन में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम आरएसएस के उत्तरबंगा प्रांत द्वारा संगठन की शताब्दी समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसे पूरे देश में मनाया जा रहा है। उत्तर बंगाल के आठ जिलों के बड़ी संख्या में युवाओं के साथ–साथ पड़ोसी राज्य सिक्किम के प्रतिभागियों के भी सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है। डॉ. भागवत कल ही सिलीगुड़ी पहुंचे हैं और वे सुबह लगभग 11 बजे सभा को संबोधित करेंगे। सैकड़ों स्वयंसेवक और आयोजक तैयारियों में जुटे हुए हैं और मंच एवं कार्यक्रम स्थल पूरी तरह से तैयार है। आरएसएस प्रमुख का भाषण सुनने के लिए सुबह से ही 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के हजारों लड़के–लड़कियां कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। आरएसएस प्रवक्ता समीर कुमार घोष ने बताया

कि इस कार्यक्रम में 15 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं की भागीदारी की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मूल रूप से, प्रत्येक जिले से 15 से 35 वर्ष की आयु के युवा लड़के–लड़कियों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। उन्हें संबोधित किया जाएगा और आने वाले दिनों में युवाओं के दायित्वों और कर्तव्यों के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे देश के लिए युवाओं की क्या भूमिका है... यदि युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन दिया जाए, तो देश भी प्रगति करेगा। युवा सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक हिस्सा है।

सीएम नीतीश कुमार ने 34 चलंत फॉरेंसिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

पटना, (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को साक्ष्य संग्रहण एवं अपराध के अनुसंधान में सहायता के लिए 34 चलंत फॉरेंसिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने फॉरेंसिक वाहनों को रवाना करने के पूर्व वाहनों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 के बाद से ही विधि व्यवस्था के

संधारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कानून का राज स्थापित किया गया, इसके लिए कई काम किए गए। अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। आपराधिक मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए 34 नए मोबाइल फोरेंसिक वाहनों का लोकार्पण किया गया है। ये सभी वाहन आधुनिक जांच उपकरणों से युक्त हैं। उन्होंने कहा कि इन वाहनों की मदद से अपराध के घटना स्थल पर पहुंचकर तत्काल जांच शुरू की जा सकेगी। इसके पहले कोई अपराध होने पर घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र कर जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजना पड़ता था। इसमें काफी समय लगता था और विलंब होने के कारण पीड़ित परिवारों में असंतोष रहता था। अब मोबाइल टीम घटना स्थल पर ही जांच शुरू कर देगी जिससे काफी सुविधा होगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित रहे।

हम भारतीय विविधता का सम्मान करते हैं : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओमान दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत–ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समझौते से 21वीं सदी में भारत–ओमान की साझेदारी में नया विश्वास और उत्साह का संचार होगा। ओमान की राजधानी मस्कट में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम एक परिवार की तरह इकट्ठा हुए हैं। भारत में विविधता है, जो हमारी संस्कृति का मजबूत आधार है। हमारे लिए हर दिन एक नया रंग लेकर आता है, हर मौसम एक नया उत्सव बन जाता है, हर परंपरा एक नई सोच के साथ आती है। यही कारण है, हम भारतीय कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, हम विविधता का सम्मान करते हैं। हम वहां की संस्कृति, वहां के नियम कायदों के साथ घुल मिल जाते हैं। ओमान में आज मैं यही होते हुए देख रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा, श्भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को हाल ही में एक और अद्भुत सम्मान मिला है। यूनेस्को ने दिवाली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। अब दिवाली का दीया हमारे घर को ही नहीं, पूरी दुनिया को रोशन करेगा। ये दुनियाभर में बसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। दिवाली की ये वैश्विक पहचान हमारी उस रोशनी की मान्यता है, जो आशा, सद्भाव और मानवता के संदेश को, उस प्रकाश को फैलाती है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम सब यहां भारत–ओमान मैत्री पर्व भी मना रहे हैं। ये मैत्री पर्व दोनों देशों की दोस्ती और हमारी साझा सांस्कृतिक और समृद्ध भविष्य का उत्सव है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ष्भारत का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है। हम ओमान की स्पेस की उम्मीदों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। 6–7 साल पहले, हमने स्पेस कोऑपरेशन पर एक एग्रीमेंट साइन किया था। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ने इंडिया–ओमान स्पेस पोर्टल डेवलप किया है। अब हमारी कोशिश है कि ओमान के युवाओं को भी इस स्पेस पार्टनरशिप से फायदा मिले।

सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो म्यूजियम का किया उद्घाटन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर अत्याधुनिक दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेट्रो के पर्यावरण और सार्वजनिक परिवहन में योगदान को सराहा और कहा कि मेट्रो ने दिल्ली की सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम करने और प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने मेट्रो टीम को बधाई दी और उल्लेख किया कि जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो की योजना को मंजूरी दी थी, उस समय किसी को विश्वास नहीं था कि भारत में मेट्रो इतनी सफल होगी। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस म्यूजियम में भारत की सबसे उन्नत

शहरी परिवहन प्रणाली, दिल्ली मेट्रो, के 30 वर्षों के सफर को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो ने दिल्ली के पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने और परिवहन प्रणाली को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी के मेट्रो–विजन को याद करते हुए कहा कि आज राजधानी में लगभग 400 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है, 289 स्टेशन हैं और प्रतिदिन 35–37 लाख यात्री मेट्रो का उपयोग करते हैं। इस उपलब्धि ने दिल्ली में यात्रा और जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो ने दिल्ली की सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम करने और प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अधिक से अधिक मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, ताकि दिल्ली और अधिक स्वच्छ, हरी–भरी और सतत विकासशील शहर बन सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो मॉडल क्लीन, ग्रीन और आत्मनिर्भर दिल्ली के लिए एक बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन न केवल मेट्रो की उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए शहरी परिवहन, इंजीनियरिंग और नवाचार की प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो ने दिल्ली को एक श्फ्यूचर रेडी सिटीश् की दिशा दी है।

दक्षिण अफ्रीका मैच न हो पाने की वजह कोहरा नहीं बल्कि प्रदूषण है : अखिलेश यादव

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ में भारत दक्षिण अफ्रीका टी20 मैच रद्द होने का परोक्ष रुप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जिम्मेदार ठहराते हुये समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि क्रिकेट मैच न हो पाने की वजह कोहरा नहीं बल्कि प्रदूषण था क्योंकि भाजपा सरकार ने शुद्ध हवा के लिये बनाये गये पार्कों को बरबाद कर दिया है। अखिलेश यादव ने बुधवार देर रात एक्स पर पोस्ट किया " दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुँच गया है। इसीलिए लखनऊ में आयोजित होनेवाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो पा रहा है। दरअसल इसकी वजह कोहरा या फॉग नहीं, स्मॉग है। हमने जो पार्क लखनऊ की शुद्ध हवा के लिए बनवाए थे, भाजपा सरकार वहाँ भी इंवेटबाजी

करवाकर उन्हें बर्बाद करना चाहती है। भाजपाई न इंसान के सगे हैं, न पर्यावरण के। मुँह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं।"गौरतलब है कि भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच बुधवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर घने कोहरे के कारण देर रात रद्द कर दिया गया था। भारत पांच मैचों की श्रृखंला में 2–1 से आगे है। सीरीज का पांचवा और अंतिम मुकाबला शुक्रवार को अहमदाबाद में खेला जायेगा।

पंजाब में जिला परिषद, पंचायत समिति चुनाव में 'आप' को बढ़त, मतगणना जारी

पंजाब, (एजेंसी)। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। 22 जिला परिषदों के 347 जोन और 153 पंचायत समितियों के 2,838 जोन में प्रतिनिधियों को चुनने के लिए 14 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। दिन भर चली वोटिंग में 48 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें 9,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल सहित प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों ने पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा। वोटिंग से पहले, कांग्रेस और ने सत्ताधारी का आरोप लगाया था, जिसमें सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके विपक्षी उम्मीदवारों को

नॉमिनेशन फाइल करने से रोकने का आरोप लगाया गया था, और कथित तौर पर कुछ नॉमिनेशन रद्द भी कर दिए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि मतपत्रों की गिनती अभी जारी है, इसलिए पूर्ण परिणाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। अब तक घोषित रुझानों और परिणामों के अनुसार, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के अधिकतर क्षेत्रों में 'आप' आगे है। कांग्रेस दूसरे स्थान पर, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल (शिअद) का स्थान रहा। जिला परिषदों में, आम आदमी पार्टी ने 60 से अधिक क्षेत्रों में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 10 से अधिक क्षेत्रों में, शिअद तीन क्षेत्रों में, भाजपा एक क्षेत्र में आगे रही और दो क्षेत्र निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीते। पंचायत समितियों में सत्ताधारी पार्टी 1,000 से अधिक क्षेत्रों में आगे थी, उसके बाद कांग्रेस 250 से अधिक क्षेत्रों में, शिअद 170 से अधिक क्षेत्रों में, भाजपा 25 से अधिक क्षेत्रों में और अन्य पार्टियां 65 क्षेत्रों में आगे थीं। बाइस जिला परिषदों के 347 क्षेत्रों और 153 पंचायत समितियों के 2,838 क्षेत्रों के सदस्यों के चुनाव के लिए 14 दिसंबर को मतदान हुआ था।

बापू का अपमान कर रहा विपक्ष : शिवराज सिंह

नई दिल्ली।, (एजेंसी)। संसद में आज विपक्षी दलों के हंगामे के बीच शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी–राम–जी विधेयक पर विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार का जवाब सुनना ही नहीं चाहता। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सरकार की तरफ से जारी आंकड़े पेश करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने फंड का दुरुपयोग किया, लेकिन हमारी सरकार ने विकास कार्यों पर खर्च करने पर जोर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि सरकार किसानों के साथ–साथ गरीबों के कल्याण के लिए विधेयक लाई है, जिसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सबसे पहले इस पवित्र सदन में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस विषय पर हमने माननीय सदस्यों के विचार सुने हैं। अब जवाब देना मेरा अधिकार है। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। मैंने रात के डेढ़ बजे तक माननीय सदस्यों की बात सुनी है। अपनी बात सुना देना और फिर जवाब न सुनना ये लोकतांत्रिक परंपराओं को तार–तार करना है। संविधान की धज्जियां उड़ाना है। ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो और हमारी न सुनो। ये भी हिंसा है। यह बापू के आदर्शों की हत्या करने का काम कांग्रेस और बाकी विपक्ष कर रहे हैं। हम गांधी के आदर्शों पर चलने वाले लोगरू कृषि मंत्री उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं पूज्य बापू (राष्ट्रपति महात्मा गांधी) के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। बापू हमारी श्रद्धा हैं। बापू जी हमारे आदर्श हैं। बापू हमारी प्रेरणा हैं। बापू हमारे विश्वास हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी ने अपने पंच निष्ठाओं में गांधी के सामाजिक–आर्थिक दर्शन को स्थान दिया है। हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। गांधी जी ने ही कहा था कि गांव भारत की आत्मा है। अगर गांव मर जाएंगे, भारत मर जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा, यह गांवों के विकास का विधायक है। माननीय प्रतिपक्षी सदस्यों ने कई तरह के आरोप लगाए। एक बात यह कही कि हम भेदभाव करते हैं। सारा देश हमारे लिए एक है। चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश–अपनी माटी। अलग भाषा–अलग वेष, फिर भी अपना एक देश।

संपादकीय

भारत को ज्यादा महत्त्वपूर्ण नहीं मानता अमेरिका

ट्रंप प्रशासन की नई सुरक्षा रणनीति में चीन का मुकाबला करने लिए अमेरिका को तैयार करने पर खासा जोर दिया गया है। मगर ऐसा लगता है कि इस मकसद को हासिल करने में अमेरिका अब भारत को ज्यादा महत्त्वपूर्ण नहीं मानता। चर्चा तो काफी समय से थी, लेकिन अब इसकी औपचारिक घोषणा हो गई है। डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है, जिसमें पहली प्राथमिकता पश्चिमी गोलार्द्ध में अमेरिकी प्रभाव को सुरक्षित करने को दी गई है। हालांकि चीन का आर्थिक एवं रणनीतिक रूप से मुकाबला करना अभी अमेरिका की प्रमुख नीति रहेगी, मगर पश्चिमी गोलार्द्ध यानी लैटिन अमेरिका और कैरीबियन द्वीप– समूह में अमेरिकी वर्चस्व को पुनर्स्थापित करना ट्रंप प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी। जाहिर है, इस लक्ष्य के अनुरूप अमेरिका ने अपनी फौरी और दीर्घकालिक रणनीतियों में बदलाव का इरादा जताया है। इससे सबसे बुरी तरह प्रभावित यूरोप और भारत होंगे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2017 में जारी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में भारत को अमेरिका की इंडो–पैसिफिक रणनीति में प्रमुख स्थान दिया गया था। कहा गया थारू हम भारत के एक अग्रणी वैश्विक शक्ति और मजबूत रणनीतिक एवं रक्षा साझेदार के रूप में उभरने का स्वागत करते हैं। इसके विपरीत ताजा दस्तावेज में केवल यह कहा गया है कि अमेरिका को भारत के साथ वाणिज्यिक (एवं अन्य) संबंधों में सुधार जारी रखना चाहिए, ताकि वह इंडो–पैसिफिक सुरक्षा में योगदान दे सके। पूरे दस्तावेज में क्वाड का केवल एक बार संक्षिप्त उल्लेख हुआ है। जबकि इस समूह के साथ जुड़ाव को अमेरिकी रणनीति में भारत के बढ़े महत्त्व के साथ जोड़कर देखा जाता था। 2017 की रणनीति के उलट नए दस्तावेज में पाकिस्तान पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। दस्तावेज में चीन के बरक्स अमेरिका की बढ़ती गई कमजोरियों का उल्लेख है और उसका मुकाबला करने लिए अमेरिका को तैयार करने पर खासा जोर दिया गया है। मगर ऐसा लगता है कि इस मकसद को हासिल करने में अमेरिका अब भारत को ज्यादा महत्त्वपूर्ण नहीं मानता। उधर अमेरिका की नई रणनीति में यूरोप का महत्त्व भी घटा है। इसके मुताबिक रूस के साथ रणनीतिक स्थिरता को फिर स्थापित करना अमेरिका का मूलभूत हित है। यूक्रेन युद्ध पर यूरोपीय नेताओं के रुख की इसमें तीखी आलोचना की गई है। यानी ट्रंप प्रशासन ने अपनी रणनीति में भारत की तरह यूरोप का दर्जा भी गिरा दिया है।

बेहतर प्रदर्शन से विधानसभा चुनावों में खुलेगी राह

उमेश

केंद्रीय सत्ता पर ग्यारह वर्षों से लगातार काबिज भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत के चार राज्य प्रश्न प्रदेश रहे हैं। कर्नाटक में उसकी सत्ता आती–जाती रही है। आंध्र प्रदेश में अकेलेदम उसके सांसद और विधायक जीतते भी रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके और अन्नाद्रमुक के साथ दो बार चार सांसद लोकसभा पहुंचाने में भी कामयाब रही। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण केरल रहा है। लेकिन लगता है कि अब दक्षिण के इस दुर्ग में भी अहम सेंध लगाने में राष्ट्रवादी पार्टी कामयाब हो चुकी है। वामपंथ के गढ़ राज्य की राजधानी तिरुअनंतपुरम् नगर निगम पर कब्जे के साथ भाजपा ने ना सिर्फ इतिहास रच दिया है, बल्कि खुद की उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं। सुरम्य वादियों और साफ–सफ्फाक समुद्री तटों के साथ हरियाली के चलते केरल को 'भगवान का अपना देश' भी कहा जाता है। इस केरल की 54 प्रतिशत जनसंख्या हिंदू है, जबकि करीब साढ़े फीसद आबादी मुसलमान है। बाकी करीब 19 प्रतिशत ईसाई हैं। भगवान के अपने देश और जनसांख्यिकी आंकड़ों के लिहाज से केरल भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद भूमि रहा है। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी अब तक बड़ी करामात नहीं दिखा पाई है। बेशकर राष्ट्रीयय स्वयंसेवक संघ यहां काफी सक्रिय है। फिर भी यहां की राजनीति दो ध्रुवीय रही है। एक तरह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी–सीपीएम की अगुआई वाला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुआई वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा। भाजपा यहां तीसरा कोण बनाने की कोशिश अरसे से करती रही है। लेकिन उसे पहली बार सफलता साल 2016 के विधानसभा चुनावों में मिली। तब पार्टी के वरिष्ठ नेता ओ राजगोपाल तिरुअनंतपुरम् सीट से चुने गए। तब पार्टी को करीब दस फीसद वोट मिला, लेकिन अगले यानी 2021 के चुनावों में पार्टी को मायूसी हाथ लगी। लेकिन वोट बढ़कर करीब बारह फीसद हो गए। 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी की उम्मीद जगी, जब लोकप्रिय मलयाली अभिनेता सुरेश गोपी त्रिशूर सीट से पार्टी के टिकट पर विजयी हुए। गोपी इन दिनों केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। बेशक पार्टी को केरल में लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट मिली, लेकिन पार्टी की वोट हिस्सेदारी बढ़कर 16 हो गई। लोकतांत्रिक राजनीति में सोलह प्रतिशत वोट मामूली बात नहीं होती। कह सकते हैं कि इसके बाद ही पार्टी की उम्मीदों को परवान चढ़ना शुरू हुआ। राज्य में बीजेपी की कमान राजीव चंद्रशेखर के हाथ है। केरल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के लिए उनकी अगुआई में पार्टी ने जमकर पसीना बहाया। इसका नतीजा राजधानी तिरुअनंतपुरम् नगर निगम पर पार्टी का तकरीबन कब्जे के रूप में सामने आया है। तिरुअनंतपुरम् नगर निगम में 101 वार्ड हैं, जिनमें से 50 पर पार्टी के पार्षद जीते हैं। पैंतालिस सालों से इस निगम पर जिस वाममोर्चे का कब्जा रहा, उसे महज 29 सीटें मिलीं हैं, जबकि कांग्रेस की अगुआई वाले मोर्चे को 19 सीटें मिली हैं। बाकी दो सीटों पर निर्दलीयों ने बाजी मारी है। केरल की राजनीति की जिसे समझ है, उन्हें पता है कि यहां वाममोर्चा और कांग्रेस साथ नहीं आ सकते। ऐसे में निर्दलीयों के समर्थन से बीजेपी का मेयर चुना जाना तकरीबन तय है। पार्टी ने कोझिकोड और कन्नूर जैसे वामपंथी गढ़ों में भी सेंध लगाने में कामयाब हुई है। यहां पार्टी ने क्रमशः 13 और 4 सीटें जीतीं हैं। पिछली बार पलक्कड़ नगर पालिका पर उसका कब्जा हुआ था और उस पर उसने अपना नियंत्रण बरकरार रखा है। साथ ही उसने त्रिपुनिथुरा नगर पालिका को भी वाममोर्चे से छीन लिया है। हालांकि पिछली बार जीती पंडालम नगर पालिका को वाममोर्चा ने उससे छीन लिया है। बीजेपी को इस बार कुल पंद्रह फीसद से ज्यादा मत मिले हैं, जबकि उसके साथी दलों का मत प्रतिशत मिला दिया जाए तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बीस फीसद वोट हासिल हुआ है। राज्य में 941 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से पिछली पार पार्टी को 19 पर जीत मिली थी, इस बार पार्टी ने इसमें सात सीटों पर बढ़त मिली है। राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनावों के ठीक पहले राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने पार्टी को भारी जीत भले ही न दिलाई हो, लेकिन उत्साहजनक जरूर हैं। ये नतीजे पार्टी के लिए आने वाले दिनों की सफलताओं की बुनियाद हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस समर्थकों की ओर से तिरुअनंतपुरम् की जीत के लिए बीजेपी की बजाय कांग्रेस के नाराज चल रहे सांसद शशि थरूर को दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तो इसे शशि थरूर की बीजेपी की कृपा भी बताया जा रहा है। हो सकता है कि शशि थरूर की कांग्रेस नेतृत्व से मायूसी के संदेश ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की मदद की हो, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर शशि थरूर को मनाने की कोशिश क्यों नहीं हुई। वैसे जीत के चाहे जो भी कारण रहे हों, अंततरू सम्मान विजेता का ही होता है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल तो बीजेपी पर तंज भी कस रहे हैं। इस तंज में कांग्रेस की खीझ देखी जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी की बढ़त से कांग्रेस की चिंता बढ़ रही है। केरल के मौजूदा स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों के दो स्पष्ट संकेत हैं। पहला यह है कि नगरीय इलाकों में दबदबा रखने वाले वाममोर्चे के दुर्ग में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। दूसरा संदेश यह है कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की अगुआई वाले मोर्चे ने अपना दबदबा बढ़ा दिया है। वैसे भी राज्य के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस का पहले से ही ज्यादा असर रहा है, जबकि शहरी इलाकों में सीपीएम की अगुआई वाले मोर्चे का। केरल के ग्रामीण और शहरी इलाके को देश के दूसरे हिस्सों की तरह कम पढ़ी–लिखी और पढ़ी–लिखी आबादी के आधार पर नहीं बांट सकते। केरल में शत–प्रतिशत साक्षरता है। इसका मतलब यह है कि वहां ग्रामीण और शहरी आबादी में पढ़ाई को लेकर कोई अंतर नहीं है। फिर भी राजनीतिक समर्थक आधार को लेकर दोनों आबादी की सोच में अंतर रहा है। इसके बुनियादी कारणों में से एक कारण शहरी स्वशासन भी रहा होगा। शहरी आबादी प्रगतिशील सोच वाली रही होगी, लेकिन जिस तरह शहरों में बीजेपी ने सेंध लगाई है, उससे साफ है कि प्रगतिशील सोच वाले वर्ग में उसकी पैठ बढ़ रही है। ऐसे में बीजेपी के विस्तार से बड़ी चिंता कांग्रेस की बजाय वाममोर्चे की होनी चाहिए। वैसे भी बीजेपी के पूरे विकास को देखें तो जहां समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियां रहीं हैं, वहां बीजेपी ने उनके ही आधार वोट बैंक पर कब्जा किया है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में बीजेपी ने समाजवादी आधार वोट बैंक को खत्म कर दिया है। लेकिन इन राज्यों में उसकी बड़ी विरोधी कांग्रेस ही है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि केरल में भी भाजपा के विस्तार की कीमत वाममोर्चे का वजूद हो सकता है। अगले विधानसभा चुनावों में केरल में भाजपा भले ही बड़ी जीत ना हासिल कर सके, लेकिन वह महत्वपूर्ण उपस्थिति जरूर दर्ज कराएगी। इसका संकेत केरल के लोगों ने स्थानीय निकाय चुनावों में दे दिया है। बीजेपी इस बीच अगर नामदार चेहरे को अपने पाले में खींचने में कामयाब रहती है तो हो सकता है कि नतीजे और भी ज्यादा चौंकाऊ हों। निकाय चुनावों में चौंकाऊ कामयाबी ने भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा दिया है। कार्यकर्ता अगर उत्साह में रहते हैं तो अपने पक्ष में मतदाताओं को मोड़ने की ज्यादा दम लगाकर कोशिश करते हैं। इसका असर मतदान केंद्र पर पहुंचे उन मतदाताओं का मन अपने पक्ष में बदलने में दिखता है, जो आखिरी क्षणों तक किसी खास दल या उम्मीदवार के पक्ष में अपना मन नहीं बना पाए होते हैं। जिन्हें चुनाव विज्ञान की शब्दावली में फ्लोटिंग वोटर कहा जाता है। कई बार ये बदलाव एक सौ अस्सी डिग्री का होता है। 2014 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में मिली बीजेपी की बड़ी जीत इसका उदाहरण है। तो क्या केरल में बीजेपी भी उसी राह पर चल पड़ी है? इसका जवाब हां में है। विधानसभा चुनावों में नतीजे कैसे होंगे, यह तब देखने की बात होगी।

भारत के टेक्सटाइल की नई ग्लोबल पोजिशनिंग

गिरिराज सिंह

जब हम भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं, तो हम केवल फैक्ट्री, मशीनों और फैशन की नहीं, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों की बात करते हैं, जिनकी जिंदगी कॉटन के खेतों, हैंडलूम, पावरलूम और सिलाई मशीनों से जुड़ी है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस व्यापक सोच, दृढ़ संकल्प और निर्णायक नीतिगत सुधार को इस क्षेत्र ने देखा है, उससे आज टेक्सटाइल सेक्टर एक नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। आज जब हम टेक्सटाइल सेक्टर में लागू हालिया सुधारों के प्रभाव की बात करते हैं, तो यह केवल बदलाव नहीं, बल्कि किसानों, उद्यमियों, महिलाओं, बुनकरों, तकनीशियनों और युवाओं की नई संभावनाओं की कहानी है जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक टेक्सटाइल शक्ति बनाना है। यह लेख सिर्फ योजनाओं की सूची नहीं, बल्कि उस परिवर्तन की झलक है जिसे हम सब ने मिलकर आकार दिया है। किसान–केंद्रित बदलाव रू कॉटन की रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट और रूस्क्क में ऐतिहासिक वृद्धि टेक्सटाइल क्षेत्र की जड़ें खेत में हैं और किसान इस यात्रा की पहली कड़ी हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकता हमेशा यह रही कि कॉटन किसान को बाजार के उतार–चढ़ाव, दामों की अनिश्चितता और बिचौलियों की दबाव–प्रणाली से मुक्त किया जाए। यही कारण है कि 2004 से 2014 के बीच जहाँ सरकारी एजेंसियों द्वारा कुल 173 लाख कॉटन बेल्स की खरीद हुई, वहीं 2014 से 2024 के बीच यह बढ़कर 473 लाख कॉटन बेल्स पर पहुँची। यह लगभग 173त्न की वृद्धि है, जो दर्शाती है कि सरकार ने किसान को सिर्फ मौसमी प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि उसे स्थायी सुरक्षा दी। इसी तरह एमएसपी में सुधार भी किसानों को स्थिरता देने वाला बड़ा कदम रहा है। 2013–14 में कॉटन का एमएसपी 3,700 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि 2025–26 में इसे बढ़ाकर 7,710 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। यह 108त्न की वृद्धि है, जो किसान की आय, सुरक्षा और आत्मविश्वास को मजबूत करती है। जब हम कहते हैं कि किसान हमेशा सुरक्षित है, तो यह सिर्फ बात भर नहीं, बल्कि इन वास्तविक आँकड़ों पर आधारित सच्चाई है कि सरकार पहले से अधिक मात्रा में कॉटन खरीद रही है और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कर रही है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटीरू क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और न्यू ऐज फाइबर सिर्फ ज्यादा प्रोडक्शन ही काफी नहीं, बेहतर क्वालिटी भी उतनी ही जरूरी है। इसी सोच के साथ ?2,500 करोड़ का मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य केवल प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं, बल्कि कॉटन की गुणवत्ता को विश्व–स्तर तक पहुँचाना है। इस मिशन के तहत बेहतर बीज, वैज्ञानिक खेती, फार्म मैनेजमेंट और गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रियाएँ मजबूत की जा रही हैं। इसके साथ ही किसान को न्यू–एज फाइबर की तरफ प्रेरित करने का प्रयास भी किया जा रहा है ताकि भारत ग्लोबल वैल्यू–चेन में हाई क्वालिटी कॉटन और मिक्स्ड फाइबर के प्रमुख सप्लायर के रूप में उभरे। जब हम भविष्य की बात करते हैं, तो पुनरू स्पष्ट करना आवश्यक है कि टेक्सटाइल की अगली वृद्धि ट्रेडिशनल फाइबर पर ही आधारित नहीं होगी। इसी दिशा में सरकार ने फ्लैक्स, रैमी, सिसल और मिल्कवीड जैसे न्यू ऐज फाइबर को प्राथमिकता में रखा है। यह फाइबर किसानों के लिए कम लागत के साथ अधिक आय देने वाले अनुकूल विकल्प हैं और इनसे पूरी वैल्यू–चेन में नई प्रोसेसिंग, नए उद्योग और बड़े पैमाने पर नए रोजगार पैदा होंगे। मिल्कवीड जैसे पौधे अब न्यू–एज टेक्सटाइल फाइबर के रूप में उभर रहे हैं और निकट भविष्य में ये किसानों के लिए अतिरिक्त आय का निश्चित ही महत्वपूर्ण स्रोत बनेंगे। कॉटन पर इम्पोर्ट ड्यूटी में राहत से उद्योग को स्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा कॉटन पर इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला उद्योग के लिए तुरंत राहत देने वाला कदम साबित हुआ है। पहले यह राहत 30 सितंबर तक ही दी गई थी, लेकिन इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इसे 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। इस कदम से मिल्स को इंटरनेशनल कम्पेटिटिव दामों पर कॉटन मिलने लगा, जिसकी वजह से यार्न और फैब्रिक की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई जो सीधे तौर पर हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाने वाली साबित होगी। स्रूश्वह्य के लिए यह कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी में राहत मिलने से अब उन्हें स्थिरता, बेहतर प्लानिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट का अवसर मिलेगा। साथ ही, डोमेस्टिक मार्केट में भी रॉ कॉटन की आपूर्ति होगी, जिससे हैंडलूम, पावरलूम, डिजाइनर सेगमेंट, और फैब्रिक आधारित स्टार्टअप तक सभी को हाई क्वालिटी फाइबर उचित मूल्य पर उपलब्ध हो पाएगा।

अमीरी की जीवनशैली, प्रदूषण का बोझ और गरीब की त्रासदी

ललित

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आज जिस घातक पर्यावरण संकट से गुजर रही है, वह केवल एक शहर की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश के लिये चेतावनी है। विडंबना यह है कि इस संकट के नाम पर जो तात्कालिक उपाय लागू किए जाते हैं, उनका सबसे बड़ा खामियाजा वही तबका भुगतता है, जिसकी इसमें सबसे कम भूमिका होती है–गरीब और श्रमिक वर्ग। इसी पीड़ा को शब्द देते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अमीरों की जीवनशैली से पैदा हुई मुश्किलों का सामना गरीबों को करना पड़ता है। यह टिप्पणी न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और नैतिक चेतना को झकझोरने वाली भी है। दिल्ली–एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह मर्मस्पर्शी टिप्पणी की। वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायमित्र अपराजिता सिंह की दलीलों पर गौर करते हुए अदालत ने स्पष्ट कहा कि ग्रैप–4 जैसी सख्त पाबंदियों का सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ता है। निर्माण कार्य रुकते हैं, दिहाड़ी मजदूरों की रोजी–रोटी ठप हो जाती है, जबकि प्रदूषण पैदा करने वाली जीवनशैली में शामिल संपन्न तबके पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता। मुख्य न्यायाधीश ने साफ शब्दों में कहा कि समस्या की जड़ अमीरों की जीवनशैली है और समाधान भी वहीं से शुरू होना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अदालत ऐसे प्रभावी और लागू करने योग्य आदेश पारित करेगी, जिन्हें जरूरत पड़ने पर सख्ती से लागू भी किया जा सकेगा। जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि महानगरों में लोगों की अपनी अलग जीवनशैली होती है, जिन्हें वे बदलना नहीं चाहते। यही वजह है कि समस्या अमीरी की वजह से होती है, लेकिन झेलना गरीब को पड़ता है। दरअसल, अदालत की सोच रही है कि हमारा परिवेश– र्यावरण साफ–सुथरा रहे, इसके लिये हम सबको अपने कुछ सुखों का त्याग करना होगा, अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल ढालना होगा एवं प्रकृति–एवं पर्यावरण के प्रति सकारात्मक रवैया अपना होगा। यह जानते हुए कि पर्यावरण पर आने वाले संकट व प्रदूषित हवा का अमीर–गरीब पर समान असर पड़ता है फिर भी अमीर लोग इससे बेपरवाह रहते हैं। निस्संदेह, शीर्ष अदालत ने समाज की दुखती रग पर हाथ रखा है। चौड़ी होती सड़कें, नए फ्लाईओवर और हाईवे बनने के बावजूद जाम और प्रदूषण कम नहीं हो रहे। कारण साफ है निजी वाहनों का बेहिसाब इस्तेमाल। एक व्यक्ति, एक कार का चलन न केवल सड़क की जगह घेरता है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी कई गुना बढ़ाता है। कभी ऑड–इवन जैसी योजनाओं पर चर्चा हुई, कार–पूलिंग की बात चली, लेकिन सार्वजनिक परिवहन को सस्ता, सुगम और भरोसेमंद बनाने की इच्छाशक्ति लगातार कमजोर रही। आज एसी, कूलर और अन्य वातानुकूलन साधनों का बढ़ता उपयोग भी पर्यावरण संकट को गहराता जा रहा है। इससे बिजली की खपत बढ़ती है, तापमान में वृद्धि होती है और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण का दायरा फैलता है। उद्योगों में भी पर्यावरणीय नियमों का ईमानदार पालन नहीं होता। जल संकट इसका एक और क्रूर उदाहरण है–जहां झुग्गी–बस्तियों में पीने के पानी की किल्लत है, वहीं पॉश कॉलोनियों में लॉन सींचे जाते हैं, कारें धुलती हैं और स्विमिंग पूल भरे रहते हैं। कुदरत ने हवा, पानी और संसाधन सभी के लिये दिए हैं, लेकिन अमीरी के असमान दखल ने इनके वितरण को अन्यायपूर्ण बना दिया है। राजनीतिक दल एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप तो करते हैं, लेकिन ठोस और दीर्घकालिक समाधान सामने नहीं आते। अब समय आ गया है कि सरकार और जनता–दोनों अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएं। सरकार को सार्वजनिक परिवहन को मजबूत, सस्ता और आकर्षक बनाना होगा, उद्योगों पर पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन कराना होगा और शहरी विकास की नीतियों को पर्यावरण–संवेदनशील बनाना होगा। वहीं जनता को भी अपनी जीवनशैली पर पुनर्विचार करना होगा–अनावश्यक वाहन उपयोग से बचना, ऊर्जा की खपत कम करना, एसी और अन्य सुविधाओं का संयमित इस्तेमाल करना और साझा संसाधनों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाना होगा। विडंबना यह है कि सत्ताधीशों ने दिल्ली में सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को सशक्त करने को प्राथमिकता नहीं दी। यदि सार्वजनिक परिवहन सस्ता व सहज उपलब्ध होता तो शायद सड़कों पर कारों का दबाव कम होता। हाल के दिनों में संपन्न व मध्यम वर्ग में एसी व अन्य वातानुकूलन उपायों के उपयोग का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। इससे जहां प्रदूषण बढ़ाने वाली बिजली की खपत बढ़ी है, वहीं बाहर का तापमान व कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ा है। इसी तरह तमाम अमीरों द्वारा संचालित उद्योगों में उन उपायों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया जो पर्यावरण में प्रदूषण कम करने में सहायक होते हैं। सरकारों की नीतिगत विफलता इस बढ़ते वायु प्रदूषण की त्रासदी का बड़ा कारण है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए योजनाएं तो बनती हैं, पर उनमें न तो स्थायित्व होता है, न गंभीरता। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, निगरानी तंत्र कमजोर है, और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई नगण्य है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारी का बंटवारा अस्पष्ट है। हर साल सर्दियों में दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों की हवा जहरीली हो जाती है, तब कुछ दिन के लिए 'आपात कदम' उठाए जाते हैं, पर जैसे ही धुंध छंटती है, सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है। नीतियों में पारदर्शिता का अभाव और उद्योगपतियों का दबाव भी एक गहरी समस्या है। कोयला आधारित उद्योगों, पेट्रोलियम कंपनियों और निर्माण व्यवसाय से जुड़ी लॉबी सरकारों पर ऐसा प्रभाव बनाए रखती हैं कि कठोर कदम उठाना राजनीतिक दृष्टि से असुविधाजनक बन जाता है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण को हमेशा 'महंगा विकल्प' बताकर टाला जाता है, जबकि वास्तव में यह निवेश मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा में है। वायु प्रदूषण का संकट केवल वातावरण में धूल और धुएं का मामला नहीं है, यह आर्थिक अन्याय, राजनीतिक असंवेदनशीलता और सामाजिक उदासीनता का प्रतीक बन चुका है। जो सरकारें जनजीवन सुधारने का वादा करती हैं, वे हवा की गुणवत्ता सुधारने में विफल रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि वायु प्रदूषण से भारत की अर्थव्यवस्था को हर साल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दस प्रतिशत तक का नुकसान हो रहा है। यह नुकसान केवल पैसों में नहीं, बल्कि मानव संसाधन की हानि, स्वास्थ्य पर बोझ और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट के रूप में भी दिखाई देता है। अब समय है कि इस संकट को

मनरेगा को क्यों खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

डॉ. ज्ञान

मनरेगा योजना में तकनीकी हस्तक्षेप, जैसे मोबाइल ऐप–बेस उपस्थिति प्रणाली, जियो टैगिंग और आधार आधारित भुगतान प्रणाली, जो अनेक श्रमिकों को काम से बाहर कर रही है, को अब कानून में संहिताबद्ध किया जाएगा, हालांकि पूरे कार्यबल के लिए डिजिटल ढांचा तैयार नहीं है। सरकार भारत श्रम शक्ति नीति 2025, जो राष्ट्रीय रोजगार नीति होगी, के तहत डिजिटल ढांचा भी ला रही है। सरकार विकसित भारत–रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक (वीबी–जी राम जी) पेश करने के लिए तैयार है, जो वर्तमान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का खत्म करेगा जिसके तहत मांग आधारित मनरेगा योजना को जीवित रखा जा रहा है, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों पर विश्वास करें। मांग आधारित मनरेगा योजना ढांचे को खत्म कर दिया जाएगा और नए कानून के तहत एक नई श्आपूर्ति आधारित योजनाश शुरू की जाएगी।27 फरवरी, 2015 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने भारत की संसद में खुद एक बयान दिया था, श्मैं ऐसी बातें सुनता रहता हूं कि सरकार मनरेगा

को खत्म करने की योजना बना रही है, या पहले ही कर चुकी है। मुझे पता है कि आप कई क्षेत्रों में मेरे अनुभव पर संदेह करते हैं लेकिन मुझे यकीन है कि आप स्वीकार करेंगे कि मेरे पास राजनीतिक कौशल है। मेरा राजनीतिक कौशल मुझे बताता है कि मनरेगा को खत्म नहीं करना चाहिए। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा क्योंकि मनरेगा आपकी विफलता का एक जीवित स्मारक है।सचमुच, उन्होंने मनरेगा योजना को केवल जीवित रखा और उसे कभी भी उस तरह से लागू नहीं होने दिया जैसी कि इसकी मूल अवधारणा थी। साल दर साल इसके बजट में कटौती की गई और कथित तौर पर योजना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसमें कई तकनीकी और अन्य प्रक्रियात्मक तरीकों को शामिल करके कार्यान्वयन को कठिन बना दिया गया। 10 महीने पहले 18 मार्च, 2025 को राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार इस योजना को नुकसान पहुंचा रही है। वह शून्यकाल के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर योजनाबद्ध तरीके से मनरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप लगा रही थीं। सोनिया ने कहा कि श्लाखों ग्रामीण गरीबों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा जालश होने के बावजूद श्यह चिंता का विषय है कि श्वर्तमान भाजपा सरकार ने योजना को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर दिया है।श्मनरेगा के तहत सरकार को ग्रामीण बेरोजगारों को मांग पर काम देना था, एक रूपरेखा जिसे नए श्वीबी–जी राम जीश बिल के तहत खत्म किया जा रहा है, जो एक नई आपूर्ति संचालित योजना रूपरेखा पेश करेगी। किस वजह से प्रधानमंत्री को अपना मन बदलना पड़ा और वह मनरेगा को क्यों बदलने जा रहे हैं? लगता है कि उनका पोषित सपना श्कांग्रेस मुक्त भारतश की राजनीति ही इसका मूल है, और कुछ नहीं। जाहिर है इसका ग्रामीण मजदूरों से कोई लेना–देना नहीं है।वीबी–जी राम जी बिल के प्रस्ताव इसे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। नए आपूर्ति संचालित ढांचे के तहत, आवंटन एक निश्चित बजट के भीतर सीमित किया जाएगा जो केंद्र निर्धारित करेगा। इसके अलावा, रोजगार केवल केंद्र द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रदान किया जाएगा। यह हमें पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की याद दिलाता है, जिसके कारण राज्य में मनरेगा का कार्यान्वयन बंद कर दिया गया था। केंद्र ने राज्य को फंड भेजना बंद कर दिया था। अदालतों को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप कोलकाता उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने महत्वपूर्ण कानूनी फैसले दिए। जून 2025 में, कोलकाता उच्च न्यायालय ने केंद्र को पश्चिम बंगाल में इस योजना को 1 अगस्त, 2025 से फिर से शुरू करने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की। अक्टूबर 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए केंद्र की याचिका खारिज कर दी और योजना को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया। अब नया विधेयक केंद्र को यह अधिसूचित करने का अधिकार देता है कि नई योजना कहां लागू की जाएगी, जिससे न्यायिक जांच को दरकिनार किया जा सकेगा। इसका मतलब यह भी है कि देश भर के पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा का सार्वभौमिक कार्यान्वयन केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा जहां केंद्र इसे लागू करने के लिए चुनेगा।वीबी–जी राम जी बिल ने कानूनी तौर पर वायदा किए गए 100 दिनों के काम को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। यह बहुत कम है, जो किसी भी श्रमिक के लिए पूरे वर्ष अपने परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, भले ही उन्हें वास्तव में वायदा के अनुसार काम दिया जाये। याद दिला दें कि पिछले साल 2024–25 में मनरेगा मजदूरों को औसतन केवल 44.62 दिन का काम दिया गया था, जो मोदी सरकार का निराशाजनक प्रदर्शन था। इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, यह बेहद संदिग्ध है कि मोदी सरकार वायदे के मुताबिक 125 दिन का काम देगी। राज्य पहले से ही धन संकट से गुजर रहे हैं। वर्तमान में, मनरेगा के तहत, इस योजना के वित्तपोषण में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 90रू10 प्रतिशत है। हालांकि, प्रावधान के तहत, केंद्र श्रम मजदूरी का 100 प्रतिशत और सामग्री लागत का 75 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। बाकी खर्च राज्यों को वहन करना होगा। वीबी–जी राम जी विधेयक के तहत, राज्यों की हिस्सेदारी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि मोदी सरकार अपना हिस्सा 90 फीसदी से घटाकर सिर्फ 60 फीसदी करके अपनी वित्तीय जिम्मेदारी राज्यों पर डाल रही है। उत्तर–पूर्व भारत और अन्य हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के लिए, वीबी–जी राम जी बिल कहता है कि फंडिंग में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 90रू10 प्रतिशत होगी। वीबी–जी राम जी विधेयक के तहत, केंद्र के पास कथित तौर पर श्श्रम की उपलब्धता को सुविधाजनक बनानेश के लिए चरम कृषि मौसम के दौरान योजना को रोकने की शक्ति होगी।

पांच में से चल रहा सिर्फ एक कोर्ट, 15 हजार मामलों में बस तारीख पर तारीख

लखनऊ, (संवाददाता)। राज्य उपभोक्ता आयोग में सिर्फ एक कोर्ट संचालित हो रहा है, जबकि चार बंद हैं। इससे आम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। करीब 15 हजार मामले लंबित हैं। अधिकतर में रोज तारीख पर तारीख ही मिल रही है। इस स्थिति में वाद दायर करने वालों को न्याय मिलने में लंबा वक्त लग रहा है। गोमतीनगर स्थित राज्य उपभोक्ता आयोग में पांच कोर्ट हैं। प्रत्येक कोर्ट में एक न्यायमूर्ति व एक सदस्य होना जरूरी है। तभी पीठ सुनवाई कर सकती है। न्यायमूर्ति और सदस्य एक एक कर सेवानिवृत्त होते गए। नतीजतन एक एक कर कोर्ट का संचालन बंद होता गया। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव

और सदस्य सुधा उपाध्याय हैं। केवल यही पीठ मामलों की सुनवाई कर रही है। ऐसे में रोजाना 100–125 मामलों की सुनवाई हो पा रही है जबकि 15 हजार से अधिक मामले लंबित हैं। जब तक अन्य कोर्ट संचालित नहीं हो जाते तब तक सुनवाई में तेजी नहीं आएगी और लंबित मामलों की संख्या बढ़ती ही जाएगी आयोग में प्रदेश भर के मामलों की सुनवाई होती है। है। जिन मामलों में जिला उपभोक्ता आयोग फैसला सुनाता है। असंतुष्ट पक्ष राज्य आयोग में अपील करता है। सिर्फ एक कोर्ट संचालित होने की वजह से मामलों में सिर्फ तारीखें मिल रही हैं। वह भी दस–दस महीने के बाद की। इससे वाद दायर करने वालों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वह न्याय पाने के लिए आयोग का दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन उसमें वर्षों का वक्त लग रहा है। आयोग में पहले दो कोर्ट बंद हुई लेकिन तीन कोर्ट चल रही थीं। इससे मामले कम लंबित थे और लोगों को जल्द की तारीखें मिल रही थीं। लेकिन पिछले सात–आठ महीने में इन तीन में से दो और कोर्ट बंद हो गए। क्योंकि न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो गए और सदस्य का कार्यकाल पूरा हो गया। तब से दिक्कत अधिक हो गई।

19 से 25 दिसम्बर तक "सुशासन सप्ताह" का आयोजन जनपद

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । शासन के निर्देश के क्रम में दिनांक 19 से 25 दिसम्बर 2025 तक "सुशासन सप्ताह" का आयोजन जनपद में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज केन्द्र सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, जिसमें शासन द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए गए। जिसके क्रम में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया है कि सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जनपद, तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर व्यापक स्तर पर आम जनमानस को दी जाने वाली सेवाए एवं जनशिकायत के निस्तारण की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी विभाग ग्राम पंचायत स्तर पर चौपालों का आयोजन कर आम जनमानस की समस्याओं को सुनें तथा उनका प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण करें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों द्वारा आम जनमानस को दी जाने वाली सेवाएं जैसे आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, समस्त प्रकार की पेंशन, जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र, खतौनी, भूमि विवाद निस्तारण, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य सेवाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त आईजीआरएस पोर्टल एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त जनशिकायतों का भी गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से लंबित प्रकरणों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि सुशासन सप्ताह के दौरान यदि किसी विभाग द्वारा कोई नवाचार किया जाए या लंबे समय लंबित शिकायतो का निस्तारण किया जाए, तो उसकी सफलता की कहानी फोटो एवं वीडियो सहित उपलब्ध कराई जाए, ताकि उसे शासन के पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे सुशासन सप्ताह के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति हो सके।

संक्षिप्त खबरें

अयोध्या में देर रात दुकान में आग लगने से विधवा महिला हुई बेरोजगार

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में देर रात एक घटना सामने आई है। थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र अंतर्गत धर्मकांटा के पास रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग पर पेड़ के नीचे रखी एक ठेला–नुमा दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। यह घटना बीती रात लगभग 12 बजे की बताई जा रही है आग लगने से दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दुकान लगाने वाली विधवा महिला चंदा बानो का कहना है कि इस आगजनी

में उन्हें करीब 50 से 60 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। दुकान में रखा सारा सामान जल गया, जिससे उनका एकमात्र रोजगार समाप्त हो गया चंदा बानो ने बताया कि पति के गुजर जाने के बाद वह इसी दुकान के सहारे अपने तीन बच्चों का पालन–पोषण कर रही थीं। अचानक लगी आग से उनका परिवार गंभीर आर्थिक संकट में आ गया है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रात में दुकान से अचानक धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दुकान पूरी तरह जल चुकी थी।घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है पीड़ित महिला ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी योजना का शुभारंभ

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण युवाओं को आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बेहतर अवसर देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहले चरण में प्रदेश की 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। इससे अब गांव के छात्र शहरों पर निर्भर हुए बिना सिविल सर्विसेज सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।हर डिजिटल लाइब्रेरी पर लगभग 4 लाख रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसमें 2 लाख रुपये की पुस्तकों की व्यवस्था, 1.30 लाख रुपये के आईटी उपकरण और 70 हजार रुपये के आधुनिक फर्नीचर शामिल होंगे। लाइब्रेरी में ई–बुक्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो कंटेंट, क्विज और करीब 20 हजार डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध रहेगी।ग्रामीण प्रतिभाओं को डिजिटली सशक्त बनाए जाने की योजन योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 35 जिलों में पुस्तकों का चयन पूरा कर लिया गया है।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने दिया धरना

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ व शिक्षणेत्तर संघ ने बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान चेतावनी दी गई कि यदि लंबित समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो 16 जनवरी को विधान भवन का घेराव और जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक हरिश्चंद्र दीक्षित ने कहा, कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पंवार ने कहा कि योग्यता वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एलटी ग्रेट में पदोन्नति दी जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण हो।

शीतलहर व कड़ाके की ठंड के चलते जौनपुर में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल दो दिन बंद

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाशश्रीवास्तव

जौनपुर। जनपद में लगातार दो दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्तदृव्यस्त हो गया है। ठंड का सबसे अधिक प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ रहा है, जिससे उन्हें स्कूल आने–जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पहले ही विद्यालयों के समय में परिवर्तन करते हुए कक्षाएं सुबह 10रू00 बजे से दोपहर 2रू00 बजे तक संचालित करने का आदेश दिया गया था। हालांकि, आगामी दो दिनों में अत्यधिक ठंड, कोहरा एवं शीतलहर की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी मान्यता प्राप्त, गैर–मान्यता प्राप्त, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विद्यालयों को पूर्णतया बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल ने बताया कि शुक्रवार और शनिवार को सभी विद्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शनिवार को विद्यालयों में बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन शिक्षक उपस्थित रहकर मतदाता पुनरीक्षण से संबंधित कार्यों का संपादन करेंगे। जिला प्रशासन के इस निर्णय से अभिभावकों और विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली है तथा बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाए गए इस कदम की सराहना की जा रही है।

तमिलनाडु और हरियाणा की टीम चौंपियन

लखनऊ, (संवाददाता)। कुर्सी रोड स्थित गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित पांच दिवसीय 69वीं राष्ट्रीय स्कूली एथलेटिक्स चौंपियनशिप का बुधवार को समापन हो गया। बालक वर्ग में तमिलनाडु सात स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य पदकों के साथ चौंपियन बना। बालिका वर्ग में हरियाणा छह स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य के साथ अव्वल रहा। बालक वर्ग की व्यक्तिगत श्रेणी में तमिलनाडु के नील समराज टी., यूपी के मो. समीर खान और पश्चिम बंगाल के अरिजीत पाल चौंपियन बने। बालिका वर्ग की व्यक्तिगत श्रेणी में अंशू (सीबीएसई) चौंपियन बनीं। मुख्य अतिथि अपर शिक्षा निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा) मनोज द्विवेदी, अर्जुन अवार्डी हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय ने विजेताओं को सम्मानित किया। स्वर्ण पदक विजेता को मिलेंगे 75 हजार रुपये रू संयुक्त शिक्षा लखनऊ मंडल डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि सरकार ने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री विद्यालयी खेल पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें नेशनल स्कूल गेम्स के एकल वर्ग के स्वर्ण पदक विजेता को 75,000 रुपये, रजत पदक विजेता को 50,000 रुपये और कांस्य पदक विजेता को 30,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। महाराष्ट्र (चार स्वर्ण, छह रजत व चार कांस्य पदक), केरल (चार स्वर्ण, दो रजत व छह कांस्य), उत्तर प्रदेश (तीन स्वर्ण, आठ रजत और पांच कांस्य)। सीबीएसई को तीन स्वर्ण, दो रजत व एक कांस्य मिला। पश्चिम बंगाल (तीन स्वर्ण, एक कांस्य), झारखंड (दो स्वर्ण, एक रजत व दो

कांस्य), राजस्थान (दो स्वर्ण व एक कांस्य), पंजाब (एक स्वर्ण, पांच रजत और तीन कांस्य), उत्तराखंड (एक स्वर्ण, तीन रजत व एक कांस्य) असम (एक स्वर्ण, एक कांस्य), बिहार (एक स्वर्ण), केंद्रीय विद्यालय संगठन (दो रजत), दिल्ली (एक रजत, दो कांस्य) कर्नाटक (एक रजत व एक कांस्य), मध्य प्रदेश (एक रजत)। उत्तर प्रदेश को व्यक्तिगत चौंपियन में मो. समी को द्वितीय स्थान मिला। टीम चौंपियन में यूपी उप विजेता रहा। लंबी कूद में प्रदेश के शिवम को द्वितीय और सागर को तृतीय स्थान मिला।

संक्षिप्त खबरें

कोडीन कफ सिरप का सरगना 21 दिसंबर को जौनपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा रू सहायक पुलिस अधीक्षक

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर ,19 दिसंबर। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में तीन फर्म संचालकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जो जांच में नाम सामने आने के बाद से फरार हैं। इसके अतिरिक्त, दूसरे जिले से गिरफ्तार आरोपी भोला जायसवाल की भी रिमांड मिली है, जिसे 21 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सहायक पुलिस अधीक्षक गोल्डी गुप्ता, जो मामले की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख हैं, ने बताया कि कोडीनयुक्त कफ सिरप के दुरुपयोग और अवैध आपूर्ति के संबंध में सभी आरोपियों के

खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पुष्टि की कि तीन फर्म मालिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं, ताकि उन्हें जिले से बाहर या विदेश भागने से रोका जा सके। पुलिस का मानना है कि यह मामला केवल अवैध बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार एक संगठित नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। गोल्डी गुप्ता ने यह भी बताया कि आरोपियों द्वारा दायर एफआईआर रद्द करने की याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इसके बाद, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी भोला जायसवाल की रिमांड मिलने के बाद उसे 21 दिसंबर को जौनपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसआईटी भोला जायसवाल से विस्तृत पूछताछ के लिए 14 दिन की पुलिस कस्टडी का अनुरोध करेगी।

रबी अभियान में अब तक कुल 5934.00 मै टन यूरिया का वितरण किया जा चुका है

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता जौनपुर ने अवगत कराया है कि रबी अभियान 2025–26 में जनपद में यूरिया उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण का विवरण निम्नवत है। जनपद में कुल 201 बी–पैक्स समितियां कियाशील है जिनके माध्यम से रबी अभियान में अब तक कुल 5934.00 मै०टन यूरिया का वितरण किया जा चुका है। जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरान्त दिनांक 18 दिसंबर 2025 को जनपद की कुल 181 समितियों में 2041.920 मै०टन यूरिया का आवंटन किया गया है। उक्त उर्वरक स्टाक की रैक दिनांक 20 दिसंबर 2025 तक आना सम्भावित है, रैक आते ही तत्काल सम्बन्धित समितियों पर यूरिया का प्रेषण करा दिया, जायेगा। जनपद में आई०पी०एल०यूरिया की एक अन्य रैक आने की सूचना मिली है।जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत, समितियों के मॉग के अनुसार लगातार यूरिया उर्वरक प्रेषण कराया जा रहा है।

प्रदेश में विधानमंडल सत्र से, वंदे मातरम पर हो सकती है विशेष चर्चाय कार्यसीमित की बैठक

लखनऊ, (संवाददाता)। विधानमंडल के शुक्रवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के संबंध में बृहस्पतिवार को सुबह 11रू30 बजे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई है। सरकार वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर सदन में विशेष चर्चा करा सकती है। हालांकि, इस पर फैसला कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दोपहर 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें महाना सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेंगे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक, भाजपा विधानमंडल दल की बैठक 21 दिसंबर को शाम छह बजे से लोकभवन के ऑडिटोरियम में होगी। इसमें सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, सभी मंत्री, विधायक व विधान परिषद सदस्य शामिल होंगे। सरकार के सहयोगी दलों सुभासपा, रालोद, निषाद पार्टी और अद (एस) के मंत्री व विधायक भी इस बैठक में बुलाए जाएंगे।

हाईकोर्ट की टिप्पणी, सांसदों को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोकता संविधान

लखनऊ, (संवाददाता)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की नियुक्तियों को असांविधानिक घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो किसी सांसद को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने से रोकता हो। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने यह निर्णय संजय शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनाया। याचिका में 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के रूप में हुई नियुक्तियों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि शपथ ग्रहण के समय दोनों लोकसभा सदस्य थे। याची का तर्क था कि सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री अथवा उप मुख्यमंत्री पद धारण करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' के नियमों के विरुद्ध है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इन सभी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' के मुद्दे पर अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ए) के स्पष्टीकरण में मंत्रियों को इस अयोग्यता से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। अदालत ने कहा कि सांसद का पद कोई सांविधानिक पद नहीं, बल्कि एक निर्वाचित पद है, जबकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान स्वयं यह अनुमति देता है कि कोई व्यक्ति, जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, वह छह माह तक मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर रह सकता है। इस अवधि के भीतर योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया था।

कुरान याद करना अल्लाह की अमानत

लखनऊ, (संवाददाता)। इस्लामिक सेंटर सेंटर ऑफ इंडिया में आयोजित कुरानी महफिल में कुरान की तिलावत और उसे याद करने की फजीलत बयान की गई। हाफिज अब्दुल हई रशीद फरंगी महली की कुरान हिफ्ज करने के लिए दस्तारबंदी की गई। ऐशबाग ईदगाह स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में कुरानी महफिल में दारुल उलूम नदवतुल उलमा के उप प्रबंधक मौलाना अम्मार हसनी नदवी ने कहा कि इल्म फरंगी महल की विरासत है। मौलाना तारिक रशीद फरंगी महली ने कहा कि कुरान याद करना अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली बताया कि हाफिज अब्दुल हई रशीद शायद ला–मार्टिनियर कॉलेज के पहले छात्र हैं, जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई के साथ कुरान को भी याद किया। दारुल उलूम निजामिया फरंगी महल के प्रधानाचार्य मौलाना नईमुर्रहमान सिददीकी ने दस्तारबंदी करने के बाद हिफ्ज–ए–कुरान का प्रमाणपत्र दिया। हाफिज अब्दुल हई रशीद ने सूराह रहमान की आयतें पढ़ीं और उनका अंग्रेजी में अर्थ भी बताया। कार्यक्रम का आगाज अब्दुल अली रशीद ने कुरान की तिलावत से किया।

अयोध्या में स्वास्थ्य सेवाओं की गहन समीक्षा बैठक आयोजित, मुख्यमंती जन आरोग्य मेलों में सुधार पर विशेष जोर

लखनऊ, (संवाददाता)। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा अयोध्या, देवीपाटन और प्रयागराज मण्डल की स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित बैठक में की गई। अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में मण्डलायुक्त कार्यालय सभागार, अयोध्या में सुबह 10.30 बजे आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गहन समीक्षा की गई। प्रदेश के अन्य मंडलों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा शीघ्र की जाएगी।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के सक्रिय सहयोग से आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव ने समीक्षा के लिए विकसित चेकलिस्ट एवं डैशबोर्ड के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा इकाइयों में महिला और पुरुष के लिए अलग शौचालय, सिटीजन चार्टर, शिकायत पेटिका, स्वच्छ पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति और मिनी स्किल लैब की उपलब्धता पर बल दिया। औषधियों की सुचारू आपूर्ति के लिए डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से समय पर इंडेंट करने का निर्देश भी दिया गया।अपर मुख्य सचिव ने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलों का स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ अनुश्रवण करें। मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश ने शत प्रतिशत चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आवश्यकतानुसार आयुष एवं बीडीएस चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग करने का निर्देश दिया। इसके अलावा तकनीकी मानव संसाधान को तत्पर रहने, चिकित्सा इकाइयों के साइन बोर्ड और जियो टैगिंग, अग्निशमन सुरक्षा मानकों का पालन और प्री–रिकार्डेड संदेशों के प्रसारण के निर्देश भी दिए गए।बैठक से पूर्व 13–15 दिसम्बर 2025 की अवधि में अयोध्या मण्डल द्वारा प्रयागराज, प्रयागराज मण्डल द्वारा देवीपाटन और देवीपाटन मण्डल द्वारा अयोध्या मण्डल की चिकित्सा इकाइयों का स्थलीय पर्यवेक्षण किया गया। इन दलों में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य मुख्यालय के अधिकारी एवं विशेषज्ञ शामिल थे। दलों ने मण्डलों के सभी जिला चिकित्सालयों, 177 सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइयों, 523 प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों और 2743 आयुष्मान आरोग्य मंदिरध्उपकेन्द्रों का स्थलीय भ्रमण कर रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में एसेंशियल ड्रग, पेयजल, चिकित्सकीय सेवा–सुविधा, मानव संसाधन, तीमारदारों के लिए सुविधाएं, साफ–सफाई और स्वास्थ्य योजनाओं की वर्तमान स्थिति शामिल की गई।बैठक में डॉ. पिंकी जोवल, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, श्री राजेश कुमार, मंडलायुक्त,है।

जनपद के सहकारिता क्षेत्र में यूरिया उर्वरक की किसी भी प्रकार की कमी नही है।

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर जिला कृषि अधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद में रबी फसलों की बुवाई एवं सिंचाई के उपरान्त टॉपड्रेसिंग हेतु कृषकों द्वारा यूरिया की मांग तेजी से की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में 22361.00 मैट्रिक टन यूरिया उर्वरक वितरण हेतु उपलब्ध है और यूरिया की कोई कमी नहीं है। जनपद के सभी बी–पैक्स समितियों, क्रय–विक्रय समितियों, एग्री जंक्शन, आई०एफ०एफ०डी०सी० कृषक सेवा केन्द्रों के साथ ही निजी बिक्री केन्द्रों पर कृषकों को जोत–बही के आधार पर पी०ओ०एस० मशीन से यूरिया की बिक्री कराया जा रहा है। यदि किसी विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया बिक्री किया जाता है, यूरिया के साथ अन्य उर्वरक ध् उत्पाद जैसे जिंक सल्फेट, माइक्रो न्यूट्रिएण्ट, सल्फर, कीटनाशी रसायन इत्यादि टैग किया जाता है एवं कृषक को पी०ओ०एस० मशीन से रसीद नहीं दिया जाता है तो ऐसे फुटकर उर्वरक विक्रेताध्थोक उर्वरक विक्रेता के साथ ही कंपनी प्रतिनिधि के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपार्ट दर्ज कराते हुए एन०एस०ए० की भी कार्यवाही की जायेगी। कृषक भाइयों से अपील है कि अपने निकटतम बिक्री केंद्र से पी०ओ०एस० मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी जोत बही के अनुसार संस्तुत मात्रा में यूरिया उर्वरक क्रय करें तथा अपने विक्रेता से रसीद अवश्य लें। यदि किसी विक्रेता द्वारा मनमाने ढंग से बिक्री की जा रही है तो उसकी शिकायत जिला कृषि अधिकारी जौनपुर के कार्यालय में स्थापित कण्ट्रोल रूम में दूरभाष संख्या 8419021250 पर पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक दर्ज करा सकते है।

आईटीआई अलीगंज में रोजगार मेला

लखनऊ, (आरएनएस)17 दिसंबर, 2025रू योगी सरकार की युवोन्मुखी एवं रोजगारपरक नीतियों के तहत प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के निर्देश पर 19 दिसंबर, 2025 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) अलीगंज, लखनऊ में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य है ।

माघ मेला की तैयारी को लेकर एसपी रेलवे ने यातायात की मुख्य रणनीतियों से सभी को कराया अवगत

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या।माघ मेला मे रिजर्व पुलिस लाइन्स के त्रिवेणी सभागार में पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज प्रशांत वर्मा ने प्रशिक्षण पण्डाल में उपस्थित सभी अधिकारियोध्कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आप सभी को किस तरह रेलवे,पुलिस, प्रशासन मिलकर माघ मेला में यातायात नियंत्रण के लिए कलर–कोडिंग सिस्टम, डायवर्जन प्लान, समर्पित होल्डिंग एरिया, ।प्–आधारित निगरानी और साइनेजध्माइक अनाउंसमेंट जैसी रणनीतियाँ अपनाये।ताकि भीड़ को व्यवस्थित किया जा सके, ट्रेनों और प्लेटफार्मों तक सुरक्षित पहुंचना सुनिश्चित की जा सके और यात्रियों को भटकने से बचाया जा सके,खास कर प्रयागराज जंक्शन और अन्य प्रमुख स्टेशनों पर कलर–कोडिंग सिस्टम (रंग–कोडिंग प्रणाली) यात्रियों को उनके गंतव्य (जैसे लखनऊ, गोरखपुर) के अनुसार अलग–अलग रंगों के शेल्टर (लाल, नीला, पीला, हरा) में भेजा जाता है प्रत्येक रंग एक विशिष्ट रूट या ट्रेन के लिए होता है, जिससे यात्री सीधे अपनी ट्रेन तक पहुंच सकते है।डायवर्जन और होल्डिंग एरिया (मोड़ और ठहराव क्षेत्र) शहर की तरफ से आने वाले भारी यातायात को नियंत्रित करने के लिए डायवर्जन प्लान लागू होते हैं।प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों को अस्थायी होल्डिंग एरिया पर रोका जाता है।जब तक कि प्लेटफार्म पूरी तरह से भर न जाएं, ताकि भीड़ का प्रबंधन हो सके द्यवही AI–संचालित कैमरे और ड्रोन का उपयोग भीड़ की निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए किया जाता है इंटिग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से 24•7 निगरानी होती है।यात्रियों को माइक पर हर घंटे दिशा–निर्देश दिए जाते हैं।स्टेशनों पर स्पष्ट साइनेज (संकेत) लगाए जाते हैं द्यत्थ् (रेलवे सुरक्षा बल) द्वारा यात्री आश्रय स्थलों में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों के सामान की गहन जांच की जाती है।कहा कि प्रयागराज जंक्शन, छिवकी, नैनी, रामबाग, प्रयाग और झूंसी जैसे सभी प्रमुख स्टेशनों के लिए अलग–अलग योजनाएँ होती हैं द्य पुलिस अधीक्षक रेलवे और अन्य अधिकारीध्कर्मचारी एक समग्र योजना के तहत काम करते हैं, जिससे भीड़ को नियंत्रित करके, श्रद्धालुओं को सुरक्षित व व्यवस्थित यात्रा का अनुभव दिया जा सके।माघ मेला पुलिस से प्रशिक्षण शिविर में अपने अनुभव को साझा करने के लिए रेलवे प्रयागराज की टीम का पुलिस अधीक्षक माघ मेला व नोडल अधिकारी माघ मेला ने आभार व्यक्त किया।

बारुन बाजार में एटीएम में चोरी का प्रयास,एटीएम का बाहरी हिस्सा कटा

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या।इनायतनगर थाना क्षेत्र के बारुन बाजार में एक इंडिया वन एटीएम में चोरी के प्रयास की दुस्साहसिक घटना सामने आई है। बुधवार–गुरुवार की रात में चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर एटीएम मशीन को काटा परंतु नगदी ले जाने में असफल रहे।चोरी का पता गुरुवार सुबह तब चला जब एटीएम कंपनी ने मकान मालिक को फोन कर एटीएम बंद होने की सूचना दी। मकान मालिक श्याम नारायण जायसवाल ने अपने बेटे आशीष को मौके पर भेजा।आशीष ने पाया कि एटीएम को गैस कटर से काटा गया है और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चोरों ने उखाड़ दिया गया है। इसके बाद मकान मालिक ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी।सूचना मिलते ही बारुन बाजार पुलिस चौकी प्रभारी अविनाश प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी। इसके बाद दोपहर में फॉरेंसिक जांच दल की फील्ड यूनिट घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य संकलन में जुट गई।एटीएम के बगल कैफ गार्मेंट्स की दुकान में लगे सीसीटीवी में दो चोर गैस कटर मशीन के साथ एटीएम में आते और जाते दिखाई पड़े हैं फिलहाल पुलिस घटना में दो से तीन चोरों के शामिल होने की बात कह रही है और चोरों की तलाश में आसपास के अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि उनका सुराग मिल सके।

इंडिया वन एटीएम बैंक के अधिकारी मोहम्मद दानिश खान ने बताया कि चोरों ने गैस कटर की सहायता से एटीएम मशीन के वाल्ट वाले हिस्से के बाहरी हिस्से को काटा परंतु जहां नगदी रखी जाती है वहां तक नहीं पहुंच सके जिस कारण वे नगदी ले जाने में असफल रहे।

मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन के नाम पर अवैध वसूली मामले मे युवक हिरासत में,पुलिस जांच में जुटी

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या।अयोध्या जिले के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। एक मरीज के परिजन से कथित तौर पर 7,200 रुपए की मांग की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है जानकारी के अनुसार, कुमारगंज थाना क्षेत्र के मसेढ़ा गांव निवासी नरसिंह ने अपने चचेरे भाई दीपक कुमार सिंह पुत्र चंद्रेश सिंह को पित्ताशय की पथरी के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। दीपक की दूरबीन विधि से ऑपरेशन के लिए 17 दिसंबर को दर्शन नगर स्थित राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12रू30 बजे दीपक को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। इस दौरान ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक अज्ञात युवक विजय कुमार सिंह (मरीज के भाई) के पास पहुंचा और 7,200 रुपए की मांग की। युवक ने कहा कि उसने दवा मंगवाई है और डॉ. संतोष कुमार ने यह पैसा मंगवाया है। विजय कुमार ने तुरंत अपने भाई नरसिंह को इस मामले की जानकारी दी। नरसिंह मौके पर गए और युवक से पैसे की मांग का कारण पूछा। युवक ने अपना नाम शशांक और पता दर्शन नगर बताया।

अमारी अमौनी स्थित वेदांता ग्लोबल स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।गुरुवार को मया ब्लॉक क्षेत्र के अमारी अमौनी स्थित वेदांता ग्लोबल स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।इस प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक व मुख्य अतिथि राज नारायण सिंह व निर्देशक राम उग्रह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।खेल प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने पिरामिड की संरचना को प्रस्तुत किया।इसके बाद बच्चों ने 100 मी 200 मी और 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई साथ ही कबड्डी बैडमिंटन तथा ऊंची कूद का भी प्रतियोगिता हुई।इसमें चार हाउस ने प्रतिभा किया पटेल हाउस, सुभाष हाउस, तिलक हाउस और आजाद हाउस ने प्रतिभाग किया। सुभाष हाउस की संरक्षक आकांक्षा मोरिया के मार्गदर्शन में कप्तान आर्यमान उप कप्तान अपूर्वी कसौधन के नेतृत्व में सुभाष हाउस की टीम ने बाजी मारी।खेल समापन में विजेता खिलाड़ियों को प्रबंधक राज नारायण सिंह व निदेशक राम उग्रह सिंह, विद्यालय के सचिव ओमनाथ सिंह व प्रधानाचार्य नितिन पाल द्वारा विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया।उसके बाद बच्चों में मिष्ठान का भी वितरण कराया गया।इस मौके पर शिवाजी सिंह, रोहित त्रिपाठी, जयप्रकाश सिंह, संतोष सिंह, विजय कुमार सिंह, सूर्यपाल सिंह, कौशलेंद्र के साथ ही स्कूल की शिक्षिकाओं में शालिनी, ममता, रागिनी, मीनू मिश्रा, खुशी, सुमुल, ज्योति, दीपांजलि, सौम्या, रुचि, प्रिया, पूजा, इरफान, सौरभ सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

60 वार्ड मे सिर्फ 45 प्वाइंट ही चयनित,भ्रष्टाचार के चलते नहीं दिख रहा कहीं अलाव की व्यवस्था

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या –नगर निगम अयोध्या में अलाव की व्यवस्था कल 60 वार्डों में सिर्फ 45 जगह पर सुनिश्चित की गई है जोकि नाकाफी है अयोध्या के प्रमुख स्थलों तक को पॉइंट में शामिल नहीं किया गया है यह आरोप मणिराम दास छावनी वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि पांडे ने लगाया है रिशु पांडेय ने बताया मेरे वार्ड के 15 पॉइंट में एक भी पॉइंट अलाव जलने के लिए चिन्हित नहीं हुए जबकि महापौर आवास और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का स्थान भी इसी क्षेत्र में आता है, वही हनुमान कुंड वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अभय श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि अलाव जलाने की व्यवस्था में पूरी तरह कागजी कोरम पूरा किया जा रहा है, हमारे वार्ड के 16 पॉइंट में एक भी पॉइंट पर अलाव नहीं जल रहा है। नगर निगम के एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी तक नगर निगम द्वारा अलाव जलाने के लिए टेंडर ही नहीं किया गया है नगर आयुक्त के विशेषाधिकार पर कुछ प्वाइंटों पर लकड़ी जलाने की व्यवस्था कराई गई है। सत्ता पक्ष के पार्षद लगातार नगर निगम पर आरोप लगा रहे हैं महापौर से वार्ता पर उनके द्वारा बताया गया कि हम बाहर हैं कल आकर व्यवस्था देखेंगे नगर निगम में कुल 60 वार्ड है और 60 वार्डों में नगर निगम की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सिर्फ 45 पॉइंट पर अलाव जलना बेहद गंभीर विषय है। राम जन्मभूमि दर्शन हेतु लगभग डेढ़ लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं जो कि नयाघाट ,कच्चाघाट,पक्काघाट बाल्मिकी भवन, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम जन्मभूमि कार्यशाला जैसी विभिन्न जगहों पर जाते हैं इतनी कड़क ठंड में कहीं भी अलाव की व्यवस्था न का न होना जाना यह प्रशासन पर प्रस्ताव चिन्ह खड़ा करता है। वहीं कुछ स्थलों पर स्थानीय नागरिकों द्वारा लकड़ी की जगह कूड़ा इकट्ठा करके ठंड से बचने का उपाय करते देखा गया।

पलिया लोहानी ग्रांम पंचायत का विकास मॉडल बना मिसाल

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या।तहसील मिल्कीपुर क्षेत्र मे हैरिंग्टनगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत पलिया लोहानी बृहस्पतिवार को विकास की प्रयोगशाला बन गई, जब मध्य प्रदेश से आए जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने यहां पहुंचकर जमीनी स्तर पर हुए नवाचारों का प्रत्यक्ष अनुभव लिया। ग्राम प्रधान अभिषेक भद्र सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पारंपरिक अंदाज में अतिथियों का स्वागत कर गांव की विकास यात्रा से परिचित कराया। एक्सपोजर विजिट के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और डिजिटल सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में किए गए कार्यों का बारीकी से अवलोकन किया। भ्रमण की शुरुआत परिषदीय विद्यालय पलिया लोहानी से हुई, जहां स्थापित खगोलीय प्रयोगशाला ने सभी का ध्यान खींचा। बच्चों से संवाद के दौरान अतिथियों को बताया गया कि किस प्रकार आधुनिक संसाधनों से ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा मिली है।इसके पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत संचालित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र, घर–घर कूड़ा संग्रह, वर्मी व नैनो कंपोस्टिंग की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित पीडीएस गोदाम का भ्रमण कर वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और सुविधाओं की जानकारी ली गई। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत आयुष्मान आरोग्य केंद्र में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का अवलोकन किया गया, वहीं ग्राम पंचायत की डिजिटल लाइब्रेरी प्रतिनिधिमंडल के लिए विशेष आकर्षण रही। अधिकारियों को जानकारी दी गई कि डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से अब तक 22द्23 विद्यार्थियों का विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन हो चुका है, जिसे ग्रामीण प्रतिभा के लिए बड़ी उपलब्धि बताया गया। भ्रमण के उपरांत प्रतिनिधिमंडल ने पलिया लोहानी को विकास, नवाचार और जनभागीदारी का सशक्त मॉडल बताते हुए इसे अन्य ग्राम पंचायतों के लिए प्रेरणास्रोत और "आदर्श ग्राम पंचायत" की संज्ञा दी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय से मनीष, जिला समन्वयक दीपक सेन एवं अविरल पाठक, जिला परियोजना प्रबंधक उपेंद्र तिवारी, मास्टर ट्रेनर महेंद्र पाल, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, ग्राम प्रधान सचिन, विकासखंड स्तरीय अधिकारी–कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

ठण्ड के चलते कक्षा 01 से कक्षा 12 तक के विद्यालय अब प्रातः 10 बजे से 03.30 तक होंगे संचालित

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।जनपद में अत्यधिक ठण्डध्शीत लहरी के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में समस्त बोर्ड के अन्तर्गत संचालित कक्षा 01 से कक्षा 12 तक के विद्यालयों के संचालन अवधि में परिवर्तन करते हुए जिलाधिकारी अयोध्या निखिल टीकाराम फुंडे द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में जनपद में समस्त बोर्ड से संचालित विद्यालय तत्काल प्रभाव से प्रातः 09.00 बजे से अपरान्ह 03.00 के स्थान पर प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 03.30 बजे तक किया जायेगा। उपरोक्त के क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक डाक्टर पवन तिवारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लाल चन्द्र ने संबंधित को निर्देशित किया है कि उक्तानुसार विद्यालयों का संचालन कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संक्षिप्त खबरें

दो दिवसीय विधायक खेल प्रतियोगिता शनिवार को होगी शुरुआत,राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल करेंगे शुभारम्भ

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।जिले में खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से आयोजित विधायक खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन शनिवार को सुबह दस बजे डाभासेमर स्टेडियम में राष्टीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद राधामोहन दास अग्रवाल करेंगे।प्रतियोगिता को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों के पंजीकरण, मैदान की साज–सज्जा, सुरक्षा व्यवस्था और चिकित्सकीय सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। प्रतियोगिता के लिए 2000

प्रतिभागियों ने रजिस्टेशन करा लिया है। जिनका आनलाइन रजिस्टेशन नही हो पाया है। उन प्रतिभागियों के लिए स्टेडियम में ऑफ लाइन तत्काल रजिस्टेशन की व्यवस्था की गई है। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे लाना और युवाओं को खेल के माध्यम से अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करना है। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी तथा एथलेटिक्स की ट्रैक व फील्ड स्पर्धाएं शामिल रहेंगी।विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन हो सके।

अशफाक उल्ला खा मेमोरियल शहीद शोध संस्थान द्वारा वर्ष 2015 प्रतिष्ठित माटी रतन सम्मान से हुए सम्मानित

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।शुक्रवार को अशफाक उल्ला खा मेमोरियल शहीद शोध संस्थान द्वार वर्ष 2015 का प्रतिष्ठित माटी रतन सम्मान से जसिता केरकेट्टा, शिवमुर्ति तथा फरहान हनीफ सम्मानित किया गया। काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष पर आयोजित शहादत दिवस समारोह मे प्रेस क्लब मै यह सम्मान दिया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अमर शहीद अशफाक उल्ला खा के प्रपौत्र शादाब उल्ला खा ने शहीद के विचारो से अवगत कराया।उन्हने कहा कि शहीदो की लड़ाई देश को खुशहाल, सुशिक्षित, संगठित, और रोजगारपरक बनाने की थी। वह देश को एकजुट संगठित होकर समाजवादी समाज बनाना चाहते थे। उन्होने कहा कि उनके सपनो को ध्वस्त कर दिया गया।उन्होने शहीदो के सपनो का देश बनाने पर जोर दिया। संस्थान के निदेशक सूर्य कान्त पाण्डेय ने अतिथियो का स्वागत करतै हुए कहा कि क्रांतिकारी आन्दोलन मै मुखबिरी करने वालो की सम्पत्ति जप्त करके शहीदो के परिवारो मै बाटी जाए। इस कार्रवाई से देश विरोधी ताकतो को सबक मिलेगा। समारोह मे गीता देवी पाण्डेय स्मृति निबंध प्रतियोगिता मे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वालै अभिषेक त्रिपाठी, रितेश कुमार, कशफ फातिमा तथा सांत्वना पुरस्कार दिव्याशी मिश्र को दिया गया।

काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष पर निकला याद करो कुर्बानी मार्च

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या।शहीद भगतसिंह स्मृति ट्रस्ट द्वारा काकोरी एक्शन की शताब्दी (1925–2025) के अवसर पर काकोरी एक्शन के महानायक, अमर शहीद अशफाक उल्ला खघँ के शहादत दिवस पर 19 दिसम्बर को प्रातः 11,30 बजे पुष्पराज चौराहे से श्याद करो कुर्बानी मार्चश गगन भेदी नारे इंकलाब जिंदाबाद, क्रांतिकारी परंपरा जिंदाबाद,सांझी शहादत सांझी विरासत जिंदाबाद,शहीद तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचायेंगे,हमारी एकता जिंदाबाद,काकोरी के अमर शहीदों को लाल सलाम आदि नारे लगाते हुए, आदि नारे लगाते हुए फैजाबाद जेल तक निकाला गया। बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी वर्ग, लेखकों, संस्कृति कर्मियों और समाजसेवियों ने इस मार्च में हिस्सा लेते हुए कारागार स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर शहीद भगतसिंह स्मृति ट्रस्ट के चेयरमैन सत्यभान सिंह जनवादी ने कहा कि आज ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे तीन दिवसीय कार्यक्रम का समापन भी है।

उन्होंने कहा कि आज के इस संगठित मार्च का उद्देश्य काकोरी कांड के अमर शहीदों के बलिदान को याद करना है। यह हमारा कर्तव्य है कि काकोरी के शहीदों की क्रांतिकारी चेतना और मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुँचाया जाये। इस अवसर पर कवि–लेखक डॉ विशाल श्रीवास्तव ने कहा आजादी की लड़ाई के मूल्यों के साथ धर्मनिरपेक्षता, समानता और सामाजिक बराबरी के पुरोधा इन क्रांतिकारियों को याद करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। कवि–चिंतक आर डी आनंद ने कहा कि क्रांतिकारियों के जीवन और समर्पण से हमें सीख लेते हुए खघसकर नई पीढ़ी को जागरूक बनना चाहिए। जनमोर्चा की संपादक डॉ सुमन गुप्ता ने प्रगतिशील मूल्यों से लैस क्रांतिकारियों के योगदान को भारत की आजादी का सबसे अहम हिस्सा बताया। शायर मुजम्मिल फिदा ने आजादी की लड़ाई में गंगा जमुनी तहजीब के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम में बाबूराम गौड़, रामदास सरल, पूजा श्रीवास्तव, रामदुलारे बौद्ध, शिवधर द्विवेदी, शशिकांत, अखिलेश सिंह, महावीर पाल, बीएसएनएल यूनियन से तिलकराज तिवारी, सामाजिक क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष रामकुमार यादव, समाजवादी महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष अपर्णा जायसवाल, प्रशांत यादव, पल्लन श्रीवास्तव, धीरज द्विवेदी, मालती तिवारी, प्रेरणा, आलोक तिवारी, शिवांगी नंदा, आनंद सिंह, राम प्रसाद, ओमवती, गीता, रीना शर्मा, आराधना सिंह, गीता देवी, अनीता सहित बड़ी संख्या में शहर के बौद्धिक लेखक, समाजसेवी और संस्कृतिकर्मी उपस्थित रहे।

फरार आरोपी पशु तस्कर अब हेरोइन के साथ गिरफ्तार, दर्ज हैं 20 आपराधिक मामले

गोरखपुर, (संवाददाता)। चिलुआताल पुलिस ने मंगलवार देर रात मोहरीपुर–सिंहोरवा रोड स्थित अंडरपास के पास हेरोइन के साथ 25 हजार रुपये के इनामी झीनक निषाद को गिरफ्तार कर लिया। वह पिपराइच इलाके के जंगल धूषण चौकी क्षेत्र के हसनपुर गांव का रहने वाला है। आरोपी झीनक पिपराइच थाना क्षेत्र में पशु तस्करी का विरोध करने पर छात्र दीपक की हत्या के मामले में भी वांछित था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी झीनक पशु तस्करों को रास्ता दिखाने और पुलिस की गतिविधियों की जानकारी देने का काम करता था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। कोर्ट में पेश करने के

बाद उसे वहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, चिलुआताल थाना अंतर्गत मजनू चौकी क्षेत्र के मोहरीपुर–सिंहोरवा रोड स्थित अंडरपास के पास मंगलवार देर रात मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। सूचना मिली थी कि एक युवक ट्रांसपोर्टनगर से बंधे के रास्ते भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर आने वाला है। सूचना पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम झीनक निषाद बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से प्लास्टिक के डिब्बे में रखी गई 105 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि झीनक निषाद न केवल नशे के धंधे से जुड़ा था, बल्कि पशु तस्करी के नेटवर्क का भी अहम हिस्सा था। वह पशु तस्करों को सुरक्षित रास्तों की जानकारी देता था और पुलिस की गतिविधियों का इनपुट उपलब्ध कराता था। इसी नेटवर्क के चलते वह पहले से ही पुलिस के रडार पर था। बीते 15 सितंबर की रात छात्र दीपक की हत्या के मामले की जांच के दौरान एसटीएफ ने चार पशु तस्करों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें झीनक निषाद का नाम भी सामने आया था। आरोपी से पूछताछ के आधार पर मादक पदार्थ और पशु तस्करी से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। उनके खिलाफ भी साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि बरामद हेरोइन कहां से लाई गई थी ।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।